भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1676
21 सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए

मेक इन इंडिया स्कीम

1676. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मेक इन इंडिया स्कीम" के अंतर्गत रक्षा उपस्करों के उत्पादन का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) रक्षा उपस्करों के उत्पादन में पहले ही से प्राप्त कर लिये गये लक्ष्य का ब्यौरा क्या है तथा भारत रक्षा क्षेत्र उत्पादन में कब तक आत्मनिर्भर बनेगा ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

लोक सभा में दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1676 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): स्वदेशी रक्षा उपस्कर के उत्पादन हेतु लक्ष्यों का निर्णय सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है । रक्षा उपस्कर की अधिप्राप्ति, खतरे की अवधारणा, संक्रियात्मक चुनौतियों और प्रौद्योगिकीय बदलावों तथा सुरक्षा चुनौतियों के संपूर्ण परिदृश्य से निपटने के लिए सशस्त्र सेनाओं को तैयारी की स्थिति में रखने हेतु विभिन्न घरेलू विक्रेताओं के साथ-साथ विदेशी विक्रेताओं से की जाती है ।

"मेक इन इंडिया" को रक्षा क्षेत्र में विभिन्न नीतिगत पहलों के जरिए कार्यांवित किया जाता है जो रक्षा सामग्रियों के स्वदेशी अभिकल्पन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देता है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) के अनुसार, पूंजीगत अधिग्रहण के लिए खरीदो (वैश्विक) श्रेणी के स्थान पर "खरीदो (भारतीय-आईडीडीएम)", "खरीदो (भारतीय)', खरीदो और बनाओ (भारतीय), खरीदो और बनाओ 'सामरिक साझेदारी माडल' अथवा 'बनाओ' श्रेणियों को प्राथमिकता दी गई है। विगत छः वित्तीय वर्षों अर्थात 2014-15 से 2019-2020 (दिसम्बर, 2019 तक), सरकार ने पूंजीगत अर्जन की विभिन्न श्रेणियों के तहत, लगभग, 4,15,006 करोड़ रुपए मूल्य के 226 रक्षा प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की है जो रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) के अनुसार स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देता है।

कई महत्वपूर्ण रक्षा उपस्कर जिसमें 155एमएम आर्टिलरी गन प्रणाली 'धनुष', हल्के लडाकू विमान 'तेजस', 'आकाश' सतह से वायु मिसाइल प्रणाली, अटैक पनडुब्बी 'आईएनएस कलवरी', आईएनएस 'चैन्नई' इत्यादि का देश में निर्माण सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत किया जा रहा है । विगत तीन वर्षों अर्थात 2017-18 से 2019-20 में रक्षा उपस्कर की अधिप्राप्ति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(कीमत करोड़ रुपए में)

वर्ष	**भारतीय स्त्रोतों से पूंजीगत और राजस्व व्यय** (सीजीडीए से प्राप्त डाटा पर आधारित)
2017-18	54951.38
2018-19	50507.65
2019-20	63784.75

****